ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-11, No.01, November: 2024

मनरेगा– एक आर्थिक अनुशीलन
(हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा वडबली तहसील केविशेष संदर्भ में)

जगजीत सिंह शोधाथी,श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ 335801
डॉ. पवन वर्मा सह आचार्य, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ 335801
डॉ. सुनील कुमार आचार्य, माधव विश्वविद्यालय, आबू रोड पिंडवाड़ा 307026
संवादाता लेखक''जगजीत सिंह, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ 335801

सारांशः– प्रस्तुत शोध पत्र हनुमानगढ़ जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर आधारित है जो कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक से सम्बन्धित है। इस शोध पत्र में न्यादर्श गांवों में शासन द्वारा चलाये जा रहे मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न कार्य के द्वारा रोजगार, आय, जीवन स्तर में सुधार एवं संतुष्टि स्तर का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रोजगार के अतिरिक्त शासन के द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार से आय, रोजगार से आय की पर्याप्तता, रोजगार के दिवस, रोजगार की पर्याप्तता, प्रति परिवार एवं प्रति व्यक्ति रोजगार की उपलब्धता, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी आदि का अध्ययन किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मागाँधी के शब्दों में ''**भारत की आत्मा गाँवों में बसती है**'' वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता, स्वशासन की वकालत किया करते थे जो की ग्रामीण अर्थवस्था एक बुनियादी ढाँचे में ही निहित होती है, अतः बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दी जाए एवं इसी सिद्धांत पर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय बाह्यताएं व टिकाऊ रोजगार तथा आर्थिक विकास को सुदृढ़ता की ओर अग्रसर होगा।
शब्द कुंजीः– ग्रामीणी अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, बुनियादी ढांचा, पर्यावरणीय बाह्यताएं, टिकाउ रोजगार, आर्थिक विकास।

भारत गाँवों का देश है जिसकी दो तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। विकासशील देश की उन्नति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के महत्वपूर्ण योगदान में पर्यावरणीय बाह्यताएँ, टिकाऊ रोजगार तथा आर्थिक विकास सहायक होते हैं। पर्यावरण एवं आर्थिक विकास एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए है, वहीं दूसरी तरफ एक देश का आर्थिक विकास भी पर्यावरण को प्रभावित करता है जिससे एक उचित लक्ष्य को निर्धारित करके विकास के ऊँचे पायदान को प्राप्त किया जा सके। पर्यावरण एक देश की आर्थिक उन्नति में पर्यावरणीय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए आर्थिक पहलुओं को मजबूती प्रदान करता है। प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर हो रहे उपभोग तथा बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण पर्यावरणीय संसाधनों की गुणवत्ता व्यर्थ हो जायेगी, जिससे ना सिर्फ उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होगी बल्कि इसके उत्पादन में लगे समस्त सम्बन्धित बाह्यताओं में समस्या उत्पन्न होने लगेगी जिसके लिए सतत् विकास की अवधारणाओं के नियम का पालन करना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश को आत्मनिर्भर बनाने में विशेष रूप से सदैव अग्रसर रहा है। देश में उत्पादन, वितरण और प्रबंधन को एक दिशा प्रदान करती है। सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था में ग्रामीण परिक्षेत्र विगत कई दशकों से महज कच्चे माल के स्रोत रह गये है जिससे ग्रामीण रोजगार का पूरा–पूरा लाभ ग्रामीण जनसंख्या नहीं ले पा रही है, पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि कृषि, हस्तशिल्प, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर निर्भरता भी औद्योगीकरण, निजीकरण एवं विश्वव्यापीकरण के कारण समाप्ती की ओर बढ़ती चली जा रही है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि नवीन तकनीकों के प्रयोग के बावजूद संकट का सामना कर रही है।

अध्ययन के उद्देश्यः–

1. हनुमानगढ़ जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आर्थिक अध्ययन करना।
2. हनुमानगढ़ जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से सम्बन्धित पहलुओं का विश्लेषण करना।
3. हनुमानगढ़ जिले में धनात्मक बाह्यताओं का अध्ययन करना।

मनरेगा के अंतर्गत कार्यदिवस–

मनरेगा कार्यक्रम से न्यादर्श क्षेत्रों में उपलब्ध कार्य दिवस का अध्ययन किया गया है। जिसे नीचे तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है। जिसके अंतर्गत 150 दिनों का सामान्यतया कार्य (रोजगार) उपलब्ध कराया जाता है लेकिन अध्ययन से पता चलता है कि अध्यायित क्षेत्र में कुल तीन प्रकार की कार्य दिवस श्रेणी है। प्रथम 0–50,

Copyright @ 2024 Author

द्वितीय 50–100 कार्यदिवस तथा तृतीय 100 से 150 कार्य दिवस है। जिसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण के माध्यम से तथ्य ज्ञात किये गये जो तालिका क्रमांक 1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक 1– मनरेगा के अंतर्गत न्यादर्श परिवारों का कार्य दिवस

न्यादर्श तहसील	कार्य दिवस						योग	
	0–50		50–100		100–150			
	परिवार की सं.	%	परिवार की सं.	%	परिवार की सं.	%	परिवार की सं.	%
पीलीबंगा	154	19	212	27	62	8	428	54
डबली	53	8	181	23	120	15	354	46
योग	**207**	**26.47**	**393**	**50.25**	**182**	**23.27**	**782**	**100**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 1 के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि न्यादर्श तहसील पीलीबंगा और डबली में मनरेगा के अंतर्गत न्यादर्श परिवारों का कार्य दिवस 0–50 में परिवारों की संख्या 207 में 26.47 प्रतिशत है इसी क्रम में 50–100 के कार्य दिवस में परिवारों की संख्या 393 में 50.25 प्रतिशत है इसी प्रकार 100–150 कार्य दिवस में 182 परिवारों की संख्या है जो 23.27 प्रतिशत है। समंकों से यह स्पष्ट होता है की कार्य दिवस में वृद्धि होने से परिवारों की सदस्य संख्या में कमी आई है। जबकि 50–100 दिनों के कार्य दिवस में परिवारों की संख्या अधिकतम है। जो कुल सर्वेक्षित प्रतिशत का 50 प्रतिशत है।

मनरेगा कार्य के बाद किया गया कार्य–

शासन द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वर्ष में प्रत्येक पंजीकृत परिवार को 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है। वर्ष के शेष बचे हुए दिनों में न्यादर्श क्षेत्रों में परिवारों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 2 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 2 – मनरेगा के बाद किया गया कार्य

कार्य	डबली		पीलीबंगा		कुल	
	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%
कृषि	165	46	198	46	363	46
निर्माण	105	30	112	26	217	28
ठेका श्रमिक	42	12	52	12	94	12
अन्य	42	12	66	16	108	14
कुल	**354**	**100**	**428**	**100**	**782**	**100**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 2 के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि न्यादर्श तहसीलों में मनरेगा के बाद किया गया कार्य जैसे कृषि कार्य में डबली में 46 प्रतिशत है और पीलीबंगा में भी 46 प्रतिशत है। जबकि निर्माण में डबली में 30 प्रतिशत और पीलीबंगा में 26 प्रतिशत हैं। इसी क्रम में ठेका श्रमिक में डबली में 12 प्रतिशत तो पीलीबंगा में भी 12 प्रतिशत है। मनरेगा के बाद अन्य किये गये कार्य में डबली में 12 प्रतिशत तो पीलीबंगा में 16 प्रतिशत है।

मनरेगा अवधि में श्रमिकों की नियमित आयः–

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मनरेगा में कुल 150 दिवसों का रोजगार उपलबध कराये जाने का नियम है। इस अवधि में सभी क्षेत्रों में 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो पाने, नियमित रोजगार प्राप्त न हो पाने तथा अन्य तकनीकी कारणों से कुछ न्यादर्श क्षेत्रों में नियमित आय नहीं मिल पाती है। जिसके निष्कर्ष को तालिका क्रमांक 3 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्रमांक 3 – नियमित आय (मनरेगा अवधि में)

उत्तरदाता	डबली		पीलीबंगा		कुल	
	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%
हॉ	245	69	286	67	531	68

 Copyright @ 2024 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-11, No.01, November: 2024

नहीं	109	31	142	33	251	32
कुल	**354**	**100**	**428**	**100**	**782**	**100**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श तहसील डबली और पीलीबंगा में (मनरेगा अवधि में) नियमित आय प्राप्त करने वाले न्यादर्शी डबली में 69 प्रतिशत और पीलीबंगा में 67 प्रतिशत है जबकि नियमित आय (मनरेगा अवधि में) नहीं प्रापत करने वालों में डबली में 31 प्रतिशत और पीलीबंगा में 33 प्रतिशत न्यादर्शी है। अर्थात् मनरेगा से आय की प्राप्ति न्यादर्शों के लिये बहुत सहायक है।

मजदूरों को पर्याप्त आय (मनरेगा अवधि में) –

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मनरेगा में कुल 150 दिवस का उपलब्ध रोजगार से प्राप्त आय न्यादर्श क्षेत्रों में मनरेगा अवधि में आय की पर्याप्तता का विवरण तालिका क्रमांक 4 में किया गया है।

तालिका क्रमांक 4 – मजदूरों को पर्याप्त आय (मनरेगा अवधि में)

उत्तरदाता	डबली		पीलीबंगा		कुल	
	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%
हॉं	198	56	286	67	484	62
नहीं	156	44	142	23	298	38
कुल	**354**	**100**	**428**	**100**	**782**	**100**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 4 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि न्यादर्श तहसील डबली और पीलीबंगा में मजदूरों को पर्याप्त आय (मनरेगा अवधि में) डबली में 56 प्रतिशत है और पीलीबंगा में 67 प्रतिशत है जबकि आय अर्जन ना करने वाले न्यादर्शियों का 44 प्रतिशत डबली में, और पीलीबंगा में 23 प्रतिशत है। आय प्राप्त करने वालों का प्रतिशत अधिक तथा आय ना प्राप्त करने वालों का प्रतिशत कम है।

मनरेगा के पूर्व वित्तीय स्थिति–

कृषि कार्य के अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने तथा समान कार्य के लिए समान मजदूरी प्राप्त न होने, मनरेगा की पूर्व की वित्तीय स्थिति का अध्ययन की न्यादर्श क्षेत्रों को किया गया है। जिसका विवरण तालिका क्रमांक 5 में दृष्टव्य है।

तालिका क्रमांक 5 – मनरेगा के पहले वित्तीय स्थिति

दिन	डबली		पीलीबंगा		कुल	
	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%
बहुत अच्छा	38	11	81	19	119	15
अच्छा	68	19	115	27	183	24
खराब	248	70	232	54	480	61
कुल	**354**	**100**	**428**	**100**	**782**	**100**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 5 के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि न्यादर्श तहसील डबली और पीलीबंगा में मनरेगा के पहले वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में प्राथमिक सर्वेक्षण के अंतर्गत बहुत अच्छा, अच्छा व खराब के अन्तर्गत प्राप्त आँकड़ों का प्रतिशत क्रमशः तहसील डबली में 11 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, व 70 प्रतिशत है जबकि तहसील पीलीबंगा में 19 प्रतिशत, 27 प्रतिशत व 54 प्रतिशत है जो की कुल प्रतिशत का 15 प्रतिशत, 24 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है।

मनरेगा के पश्चात वित्तीय स्थिति–

कृषि कार्य के पश्चात् रिक्त समय में रोजगार मिलने के कारण वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। न्यादर्श क्षेत्रों में समान कार्य के लिए समान मजदूरी तथा एक वित्तीय वर्ष में कुल 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध होने के बाद की स्थिति का विवरण तालिका क्रमांक 6 में दिया गया है।

Copyright @ 2024 Author

 ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-11, No.01, November: 2024

तालिका क्रमांक 6 – मनरेगा के बाद वित्तीय स्थिति

दिन	डबली		पीलीबंगा		कुल	
	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%
बहुत अच्छा	231	65	272	64	503	64
अच्छा	109	31	129	30	238	31
खराब	14	4	27	6	41	5
कुल	**354**	**100**	**428**	**100**	**782**	**100**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 6 के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि न्यादर्श तहसील डबली और पीलीबंगा में मनरेगा के बाद वित्तीय स्थिति प्राथमिक सर्वेक्षण में बहुत अच्छा, अच्छा और खराब के अंतर्गत तहसील डबली में क्रमशः प्रतिशत है 65 प्रतिशत, 31 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और तहसील पीलीबंगा में 64 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार–

न्यादर्श क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होने तथा मजदूरी दर में सुधार होने के कारण न्यादर्श परिवारों की जीवन–स्तर में सुधार हुआ है या नही हुआ है का अध्ययन किया गया है। जिसे तालिका क्रमांक 7 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका क्रमांक 7 – ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार

उत्तरदाता	डबली		पीलीबंगा		कुल	
	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%	सर्वेक्षित	%
हाँ	272	77	336	79	563	72
नहीं	82	23	92	21	219	28
कुल	**354**	**100**	**428**	**100**	**782**	**100**

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण

तालिका क्रमांक 7 से प्रतीत होता है कि न्यादर्श तहसील डबली और पीलीबंगा में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार से सम्बन्धित निष्कर्ष के विश्लेषण से पता चलता है कि तहसील डबली में जीवन स्तर में सुधार का प्रतिशत 77 प्रतिशत है तो पीलीबंगा में 79 प्रतिशत है इसी क्रम में नहीं का प्रतिशत तहसील डबली में 23 प्रतिशत है और पीलीबंगा में 21 प्रतिशत है।

निष्कर्षः–

1. निष्कर्ष स्वरूप समंकों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चयनित क्षेत्र पीलीबंगा में मनरेगा का कार्य दिवस (प्रतिशत) डबली की तुलना में अधिक पाया गया है।
2. निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है की प्राप्त समंकों के आधार पर तहसील डबली और पीलीबंगा दोनों ही तहसीलों में मनरेगा के बाद किये गये कार्य में कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है और कृषि के पश्चात् सबसे अधिक प्रतिशत निर्माण कार्य में पाया गया है।
3. इस प्रकार प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि तहसील डबली और पीलीबंगा में नियमित आय (मनरेगा अवधि में) प्राप्त का प्रतिशत अधिकतम है। जो कुल सर्वेक्षित प्रतिशत का 68 है।
4. प्राप्त समंकों के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है की तहसील डबली और पीलीबंगा में मजदूरों को पर्याप्त आय (मनरेगा अवधि में) उत्तरदाताओं द्वारा हाँ का प्रतिशत अधिकतम है।
5. निष्कर्ष स्वरूप प्राप्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है की मनरेगा के पहले वित्तीय स्थिति का प्रतिशत खराब में सबसे अत्यधिक प्राप्त हुआ है। जो की कुल प्रतिशत का 61 प्रतिशत है।
6. निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि मनरेगा के पश्चात् न्यादर्शियों की स्थिति पीलीबंगा की अपेक्षा डबली में अधिक अच्छी है।
7. निष्कर्ष यह है कि डबली की तुलना में पीलीबंगा में अधिक सुधार होता परीलक्षित होता है।

अतः यह निष्कर्ष स्वरूप कहना समीचीन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना धनात्मक बाह्यताओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है जिससे अध्यायित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन तबके के लोगों को, न की रोजगार, आय की प्राप्ति होती है अपितु उनके आर्थिक जीवन में सुधार भी परिलक्षित

 Copyright @ 2024 Author

 ISSN: 2278-4632
Vol-14, Issue-11, No.01, November: 2024

होता है। इससे यह प्रतीत होता है की मनरेगा, रोजगार एवं ग्रामीण विकास परस्पर समुच्चय है जो किसी भी अविकसित क्षेत्र के लिए आवश्यक जान पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

आहूजा, उषा रानी, दुशयंत त्यागी, सोनिया चौहान और ख्याली राम चौधरी (2011),"ग्रामीण रोजगार और प्रवासन पर मनरेगा का प्रभावः–हरियाणा के कृषि–पिछड़े और कृषि–उन्नत जिलों में एक अध्ययन" कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, वॉल्यूम। 24 (सम्मेलन संख्या) 2011, पीपी 495–502।

चौधरी, विजय के. (2004) "छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में वाटरशेड विकास कार्यक्रम एमएमई का एक आर्थिक मूल्यांकन" पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ पी.पी. 1–7.

दीक्षित, ए.के. और पी.एस. बिरथल (2013) "भारत की मिश्रित कृषि प्रणालियों में पशुधन की सकारात्मक पर्यावरणीय बाह्यताएं" कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, खंड। 26(नंबर 1), जनवरी–जून 2013, पृष्ठ 21–30।

हरीश, बी.जी., एन. नागराज, एम.जी. चंद्रकांत, पी.एस. श्रीकांत मूर्ति, पी.जी. चेंगप्पा, और जी. बासवराज (2011) "कर्नाटक के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र में कृषि के लिए श्रम आपूर्ति और आय वृद्धि पर मनरेगा के प्रभाव और निहितार्थ" कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, वॉल्यूम। 24 (सम्मेलन संख्या), पीपी 485–494

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, (2013) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ और भेद्यता में कमी" प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम, GIZ, नई दिल्ली।

निवेन विनचेस्टर और सेबस्टियन रौश (2013), "नकारात्मक उत्सर्जन रिसाव की क्षमता की संख्यात्मक जांच" अमेरिकी आर्थिक समीक्षाः– पेपर और कार्यवाही 2013, वॉल्यूम। 103, क्रमांक 3, पृष्ठ 320–325।

पामर, जे. जेफरी (2003) "पर्यावरणीय स्थिरता के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों पर अनुभवों का संश्लेषण" एशियाई ग्रामीण जीवन विकास फाउंडेशन (एआरएलडीएफ), इंटरनेशनल चियांग माई थाईलैंड, पी.पी. 6–8.8– इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइलैंड एग्रीकल्चर (सी आर आई डी ए) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट (आई आई एफ एम) और जी आई जेड और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से, जहां पर इस संकलन का प्रकाशन जून 2012.

एंग्लर, एम. और एस. रवि (2012) 'वर्कफेयर एज एन इफेक्टिव वे टु फाइट पॉवर्टी : द केस ऑफ इंडियाज एन आर ई जी एस', 2012.

तिवारी आर., एच. आई. सोमशेखर, वी.आर. रामकृष्ण, आई. के. मूर्थि, एम. एस. कुमार, बी. के. कुमार, एच. पाराटे,एम. वर्मा, एस. मालवीय, ए. एस. राव, ए. सेनगुप्ता, आर. कट्टूमूरी औरएन. एच. रविन्द्रनाथ (2011) 'महात्मा गांधी नरेगा फॉर एनवायरनमेंटल सर्विस एनहेंसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी रिडक्शन : रंपिड अप्रेजल इन चित्रहनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट; कर्नाटक', इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वर्ष 14 मई 2011, खंड 66, संख्या 20.

 Copyright @ 2024 Author